July-Aug, 2009

Tax E-Chronicle

Monthly News Letter on Tax and Revenue

Commercial Taxes Department
Government of Rajasthan

From the Desk...

In federal system, Indirect taxes are the major wheels for development of the States. State are administering various Indirect taxes i.e. Value Added Tax, State Excise, Registration and Stamp duty etc. as revenue.

Tax reforms of In-direct and Direct taxes was initiated in year 1991 in the country. After detailed exercise and deliberation, Sales Tax was replaced by Value Added Tax from 2005-06. In Rajasthan, VAT was introduced in year 2006. The Journey of tax reforms is still continued and **Goods and Services Tax** is on the way to be implemented in the country

Apart from the tax reforms, department is committed to provide hassle free tax administration and better services to the taxpayers of the State. Tax payer Services as various e-Services and facilitation through **Tax Facilitation Centers** has been introduced across the State. The Tax Facilitation Centers are being strengthened and better services are being ensured by regular monitoring. I feel that this initiative is definitely improved accountability of the officials of the Department.

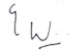

(B.N.Sharma)

Highlights

Rajasthan VAT IT Project: Awards

- Runners Up in **Govt Technology Awards 2009** (was in top 5 projects out of 500 projects in its class world-wide)
- **Plaque of Appreciation** in India-Tech Excellence Awards 2009
- Reached in Top 5 in **National E-Governance Awards 2008** across India
- Reached in Top 5 in **CS-Nihilentl Awards 2009** across India

New Innovations...

- **Bank of Baroda** has been authorised for e-Payment and dealers having account in BOB can pay tax electronically (w.e.f 14-10-2009)
- Addition of **IDBI Bank** and **Union Bank of India** is on the way and would be available for e-Payment shortly.

Wish You very Happy and Prosperous Deepawali

E-Payment for September 2009 is Rs 420.77 Cr which is 50.73% of total receipts during the Month

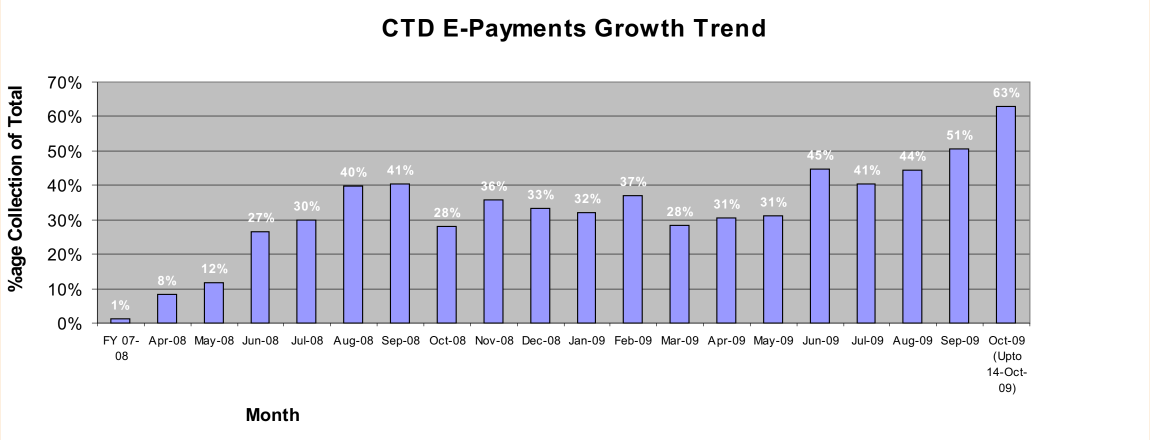

Patron
B.N. Sharma
Commissioner

Editor
H.S.Meena
Addl. Commissioner

Editorial Board
V.K. Sharma, Ramesh C. Sharma, Kirti Sharma

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 528/2008/श्रीगंगानगर

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–अ, श्रीगंगानगर, ...अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स एन.एम. एक्सपोर्ट्स, श्रीगंगानगर, ...
..............प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री ओ.पी. सहारण, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एम.पी.पारीक,

उप–राजकीय अभिभाषक..................अपीलार्थी की ओर से

श्री रामेश्वर शर्मा, अधिवक्ता..................प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 19.08.2009

निर्णय

यह अपील अपीलार्थी विभाग द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, बीकानेर के अपील संख्या 53/आरवेट/श्रीगंगानगर/07–08 में पारित आदेश दिनांक 27.12.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–अ, श्रीगंगानगर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी कहा गया है) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा गया है) की धारा 22 के अन्तर्गत प्रत्यर्थी व्यवहारी के वर्ष 2006–07 की प्रथम तिमाही के दिनांक 5.9.2006 को प्रस्तुत रिटर्न के आधार पर प्रथम तिमाही का कर निर्धारण आदेश दिनांक 29.12.2006 को पारित करते हुए प्रत्यर्थी व्यवहारी को मैसर्स रामदेव ट्रेडिंग कम्पनी, फलौदी से खरीद रू 32,90,310.49 पर इनपुट टैक्स क्रेडिट रू 72363.45 अस्वीकृत किया जाकर देय कर व ब्याज की मांग रू 34410/– कायम की गयी। सहायक आयुक्त, वृत्त–बी, वाणिज्यिक कर जोधपुर द्वारा पत्र क्रमांक 244 दिनांक 27.10.2006 के कर निर्धारण अधिकारी को जोधपुर जिले की फलौदी स्थित फर्म मैसर्स रामदेव ट्रेडिंग कम्पनी द्वारा एन.एम. एक्सपोर्ट, 48 जी ब्लॉक, श्रीगंगानगर को कर योग्य माल की बिक्री करते हुए जारी किये गये वैट इनवाईस में बोगस आई.टी.सी. क्लेम कर करवंचना का संदेह होने से बिलों की जांच व सत्यापन हेतु सूचित किया गया। तत्पश्चात् सहायक आयुक्त वृत्त बी, जोधपुर के पत्र क्रमांक 311 दिनांक 9.11.2006 से कर निर्धारण अधिकारी को यह सूचित किया गया कि मै0 रामदेव ट्रेडिंग कम्पनी, फलौदी एवं मैसर्स राकेश ट्रेडिंग कम्पनी, फलौदी की दोनों फर्मो ने फर्जी क्रय बताकर विक्रय के वैट इन्वॉयस जारी किये है। आपके वृत्त में यदि किसी व्यवहारी ने उक्त दोनों फर्मो से माल खरीदा है, तो उन्हे आई.टी.सी. स्वीकृत नहीं किया जावें। अतः इन फर्मो से क्रय किये गये माल के व्यवहारी को वैट अधिनियम की धारा 18 (3)(V) के तहत माल आई.टी.सी.(इनपुट टैक्स क्रेडिट) स्वीकृत नहीं किया जावें। सहायक आयुक्त वृत्त बी, जोधपुर से प्राप्त पत्र सूचना के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी घट द्वितीय वृत्त अ, श्रीगंगानगर से मैसर्स एन.एम. एक्सपोर्ट, 48 जी ब्लॉक, श्रीगंगानगर द्वारा मैसर्स रामदेव ट्रेडिंग कम्पनी, फलौदी से की गई खरीद की फर्म के लेखों/रेकार्ड से सत्यापन की जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई। तत्पश्चात कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यार्थी व्यवहारी को मैसर्स रामदेव ट्रेडिंग कम्पनी, फलौदी के वैट–07 में दर्शाई गई खरीद की जांच पर बिना क्रय किये गये विक्रय के वैट इनवाईस जारी करने के कारण इन पद इनपुट टैक्स क्रेडिट अस्वीकार करते हुए नियमानुसार कार्यवाही का नोटिस दिनांक 13.11.2006 जारी करते हुए सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाकर पारित किये गये कर निर्धारण आदेश दिनांक 29.12.2006 में प्रत्यर्थी व्यवहारी को फर्म मैसर्स रामदेव ट्रेडिंग कम्पनी, फलौदी से की गई खरीद पर चुकाये गये वैट पर आई.टी.सी. स्वीकृत नहीं किया गया। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश को प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, बीकानेर के समक्ष चुनौती दिये जाने पर उपायुक्त (अपील्स) के अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.12.2007 द्वारा व्यवहारी की अपील स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर यह अपील राजस्व द्वारा प्रस्तुत की गई है।

शेष अगले अंक में......

E-Payment of Tax

What is e-Payment ?

- e-Payment is payment carried out electronically using internet banking facility of your bank.
- The details of tax payment like your name, assessment period, tax amount, etc. are filled up on-line and then using the internet banking facility, the tax amount is debited from your account and credited with Govt.
- The receipt for this payment is generated electronically upon successful completion there itself.

Process of E-Payment

- e-Payment is payment carried out electronically using internet banking facility of your bank.
- The details of tax payment like your name, assessment period, tax amount, etc. are filled up on-line and then using the internet banking facility, the tax amount is debited from your account and credited with Govt.
- The receipt for this payment is generated electronically upon successful completion there itself.

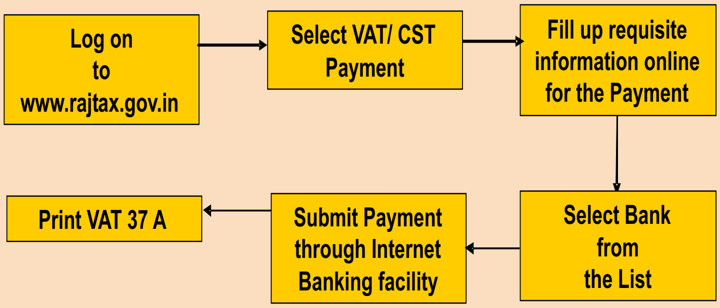

Notifications

S.No.	Notification/Circular No.	Date	Subject Matter	Comments
1.	F12(84)FD/Tax/2009-14	08-07-2009	अनुसूची V में कर दर 12.5% से बढ़ा कर 14% करना	रा.मू.क.अ., 2003 के अन्तर्गत 08.07.2009 से सामान्य कर दर 14% हो गई है। ऐसी वस्तुएँ, जो अधिनियम की अनुसूची I, II, III, IV एवं VI में वर्णित नहीं है, 14% कर दर से कर योग्य है।
2.	F12(84)FD/Tax/2009-20	08-07-2009	खादी ग्रमोद्योग इकाईयों की शर्तो के अधीन कर से छूट प्रदान करना	कुछ वस्तुओं को छोड़ कर शेष समस्त खादी ग्रामोद्योग इकाईयों को रा.मू.क.अ. 2003 के अन्तर्गत कर से विमुक्ति प्रदान की गई है।
3.	F12(84)FD/Tax/2009-21	08-07-2009	VAT-47 एवं VAT-49	समस्त कर योग्य वस्तुओं पर परिवहन के साथ VAT-47 ण्वं VAT-49 की अनिवार्यता समाप्त कर चुनिन्दा वस्तुओं पर लागू की गई है।
4.	F12(84)FD/Tax/2009-25	08-07-2009	डिजीटल सिग्नेचर	ऑनलाईन रिटर्न जमा कराने हेतु डिजीटल सिग्नेचर की अनिवार्यता को समाप्त किया गया।
5.	F12(84)FD/Tax/2009-27	08-07-2009	ऑडिट रिपोर्ट	पैट्रोलियम खूदरा आउटलैट व्यवसायियों को ऑडिट रिपोर्ट देने से विमुक्ति प्रदान की गई।
6.	F12(94)FD/Tax/2009-54	31-08-2009	मदिरा हेतु प्रशमन योजना	Foreign Liquor, IMFL एवं Beer हेतु प्रशमन योजना लागू की गई।
7.	F3(A)(10)/Juris/Tax/CCT/97/536	07-08-2009	Prosecutor should not be Judge की क्रियान्वति	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा RST. Act की धारा 77 एवं 65 तथा RVAT. Act की धारा 75 एवं 61 मे दर्ज अभियोगों का निस्तारण सम्बन्धित वृत्त के सहायक आयुक्त/वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा किया जाएगा। सहायक आयुक्त/वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा बनाए गए अभियोगों के निस्तारण हेतु अतिरिक्त आयुक्त (वैट एवं आई.टी) द्वारा अन्य वृत्त के स.आ./वा.क.अ. को पत्रावली स्थानान्तरित की जाएगी।
8.	F16(323)VAT/Tax/CCT/06/553	07-08-2009	धारा 17(2) में शीघ्र रिफण्ड	बजट घोषणा के अनुरूप ऐसे व्यवहारी जो ई–रिटर्न फाईल करते है एवं त्रैमासिक कर निर्धारण का विकल्प लिया है, को देय प्रतिदाय (रिफण्ड) का 50 प्रतिशत रिटर्न प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से 30 दिवस के भीतर देय होगा।
9.	F.120(Insp.)(inst.)Tax/CCT/85/665	01-09-2009	इनपुट टैक्स क्रेडिट का सत्यापन	वृत्ताधीन सत्यापन एक माह में, सम्भागाधीन सत्यापन तीन माह में एवं अन्तर–सम्भागीय सत्यापन छः माह में (कर विवरणी जमा कराने की तिथि से) किया जाएगा।

Data Nest...

विभाग की महत्वपूर्ण उपलब्धि

(राशि करोड़ रू. में)

क्र.सं.	मद	2008—09		2009—10		
		राजस्व लक्ष्य वार्षिक(R.E.)	उपलब्धियॉ (Tent.)	राजस्व लक्ष्य वार्षिक(B.E.)	उपलब्धियॉ माह Aug 2009 तक(Tent.)	प्रतिशत उपलब्धि
1	वैट	9100.00	8904.50	10030.00	3797.01	37.86
2	प्रवेश कर	190.00	189.90	225.00	76.38	33.95
3	मंनोरजन कर एवं विलासिता कर	60.00	64.53	70.00	16.11	23.01

TAX TOPIC

CIRCULAR

Sub: Order under sub-section (2) of section 17 of the RVAT Act, 2003

Provisions of refund to the extent of fifty percent of the refundable amount subject to the condition of subsequent verification of the deposit of refundable amount has been made, for dealers who files returns electronically and also opts for quarterly assessment under sub-section (2) of section 23, vide Rajasthan Finance Bill (Bill No. 14 of 2009).

In order to give effect to this amendment, and to provide early refund to the dealer(s) who have filed return(s) electronically and have also opted for quarterly assessment under sub-section (2) of section 23 of the Act, it is directed that where an application for claim of refund in accordance with the provisions of the rule 27 or 28, as the case may be have been submitted by the said class of dealer to the assessing authority or the officer authorised by the commissioner, refund to the extent of fifty percent of refundable amount shall be allowed in such cases within thirty days from the last date of filing of the return for the relevant quarter.

In case where refund have been issued of fifty percent of the refundable amount, the assessing authority shall take steps on priority basis to finalise the pending assessments of such dealer(s), and to verify the transactions upto first point in the series of sales, on the basis of which refund has been claimed, to ensure actual deposit of tax so refunded, and to get verified the declaration forms submitted by the dealer in support of concessional rate of tax and shall issue the refund of the balance amount.

In case genuineness of the purchase transactions in respect of which input tax credit has been claimed is not proved or refund is found to be in excess of the refund due under the Act, with a view to make repayment of such refunded amount along with interest at the rate notified under section 55 of the RVAT Act, 2003, an undertaking to this effect along with a security of fifty percent of refundable amount, in any form as prescribed under Rule 77 of Rajasthan VAT Rules, 2006, to the Satisfaction of the assessing authority shall be submitted by the dealer. Where security has been furnished by the dealer for claim of early refund in the preceding quarter(s), to the extent of amount for which the deposit of tax on transactions have been verified up to the first point in the series of sales. However, it should be ensured that at any point of time, total amount of unverified amount of input tax should not exceed the amount of security. Security shall not be demanded for the amount of refund where the deposit of tax on the transactions, on the basis of which refund has been claimed, is verified up to the first point in the series of sales. The assessing authorities shall record in writhing the fact of such verification.

The claim of concessional rate of tax will be limited to the extent of the declaration forms furnished by the dealer.

The assessing autoority shall pass speaking order for such refund. Where refund is allowed partially or disallowed, the applicant shall be afforded opportunity of being heard before passing such order. where the refund is allowed, he shall issue refund order to the applicant in the manner specified under the Rajasthan Vat Rules, 2006.

In Case where refunds have been issued, the assessing autority should take steps on priority basis to finalise the pending assessments of such dealers, to verify the transactions up to the first point in the series of sales, on the basis of which refund has been claimed, to ensure actual deposit of tax so refunded, and to get verified the declaration forms submitted by the dealer in support of concessional rate of tax.

Subsequent to the passing of such order, if it is found that refund was granted in excess of the actual refund due, such excess refunded amount shall be recovered as if it is a tax due from the dealer under this Act and the interest on such tax shall be charged at the rate notified by the State Government under section 55 of the RVAT Act, 2003 for the period from the date of grant of refund, till the date such amount is paid in the Government treasury.

A Separate register shall be maintained by each assessing authority for all the applications received for early refund and action taken thereon.

Action for issuance of such refunds should immediately be initiated and progress of the refund cases of the first fortnight of August 2009, should positively be communicated to the undersigned on 16th of August, 2009.

It should be ensured the no undue hardship is caused to the applicants and the applications are disposed of within the stipulated time. The Deputy Commissioner (Adm) shall monitor the cases of such refunds personally and shall submit the report the progress in this regard to the undersigned in the monthly D.O. Additional Commissioners shall also review a few cases of such refunds during their visits to the offices.

Revenue leader of the month.

Profile of a leading tax payer

HPCL is a dealer registered in the Special Circle, Rajasthan. It deals in petroleum products i.e Petrol, Diesel, ATF, Naptha etc. The last five years revenue figures are as follows:- (Rs. in Crore)

S.No.	Year	Revenue
1	2004-05	487.13
2	2005-06	548.49
3	2006-07	639.85
4	2007-08	710.23
5	2008-09	735.18

Presently, HPCL is making payment of tax electronically and rarely defaults in payment of tax.

DISCLAIMER

The newsletter is for general information purposes only and the contents contained herein are not meant to constitute legal advice

SUGGESTIONS & SUBSCRIPTION:

Your suggestions/queries related to newsletter/requests for free e- subscription for the newsletter are welcome at:

The Addl. Commissioner (VAT&IT)
Commercial Taxes Department
HQ, Kar Bhawan, Ambedkar Circle
Bhawani Singh Marg, JAIPUR
Ph:0141-2227291,0141-2385142
E Mail: acct-vat@rajtax.gov.in

The newsletter is also available at
Www.rajtax.gov.in